eq[;ea=h Mk- jeu flag dk lans'k x.kra= fnol 26 tuojh 2010 ykyckx ijsM eSnku] txnyiqj

fiz; HkkbZ;ksa ,oa cguksa]

गणतंत्र दिवस की गौरवमयी साठवीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सबसे पहले मैं उन महान विभूतियों को सादर नमन् करता हूं, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई और गणतंत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। आज के इस राष्ट्रीय त्यौहार को गण–पर्व भी कहा जाता है। यह जन–जन का त्यौहार है। मेरा मानना है कि देश के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान दर्ज होता है। इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं।

हम लोगों ने आजादी के बाद के छह दशक भी काफी अभावों में गुजारे हैं, लेकिन अब मैं खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि पिछले छह वर्षों के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में गर्व करने लायक बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली गई हैं। वह सारी उपलब्धियां मैं जन–जन को समर्पित करता हूं। अब कह सकते हैं कि हम उस राज्य के निवासी हैं, जो अनेक क्षेत्रों में, देश में अव्वल स्थान पर है। इससे आपके गौरव में और गरिमापूर्वक जीने के अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी।

किसी राज्य की तरक्की का सबसे बड़ा पैमाना प्रति व्यक्ति औसत आय को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में चालू मूल्यों पर वर्ष 2000–01 में प्रति व्यक्ति आय 10 हजार रूपए थी, जो कि वर्ष 2008–09 में बढ़कर 29 हजार रूपए से भी अधिक हो गई। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की यह दर देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। इसी तरह राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण पैमाना सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 18.61 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जो सभी राज्यों में सर्वाधिक है।

राज्य में औद्योगिक विकास की चर्चा हम अक्सर करते हैं लेकिन राज्य के विकास का असली मापदण्ड वहां हो रही खपत को माना जाना चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि बीते साल पूरे भारत में सीमेन्ट की औसत खपत 10 प्रतिशत बढ़ी है तो छत्तीसगढ़ में 12 प्रतिशत बढ़ी है। बीते पांच वर्षों में छत्तीसगढ में सीमेन्ट की खपत दोगुनी हो गई है। इससे पता चलता है कि राज्य में अधोसंरचना निर्माण के काम की गति कितनी तेज हुई है। राज्य में सीमेन्ट उत्पादन की वर्तमान क्षमता 11 मिलियन टन है, जो इस साल बढ़कर 17 मिलियन टन हो जाएगी। इस तरह छत्तीसगढ़ सीमेन्ट के साथ स्टील, एल्यूमीनियम तथा ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ ने लगातार अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धिया हासिल की है, लेकिन हमें इससे संतुष्ट नहीं होना है। हमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। समग्र प्रयासों से छत्तीसगढ़ को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। इस बात को मैं अटल जी के शब्दों में कहता हूं–

dej dls] cfynku djs]
tks ik;k mlesa [kks u tk,a]
tks [kks;k mldk /;ku djsaA

हमारे देश के महान संविधान में प्रत्येक देशवासी को गरिमा के साथ जीवन–यापन का अवसर देने का महान संदेश है। हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी यही है। इसलिए हमने राज्य में हर वर्ग के लोगों की हर तरह की जरूरतों को चिन्हांकित किया और उनके लिए विशेष योजनाएं लागू की गईं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा आबादी किसानों की है, जो वर्षों से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। हमने किसानों की माली हालत सुधारने का बड़ा अभियान चलाया। जिसके तहत समर्थन मूल्य पर उनका पूरा धान खरीदने, धान की कीमत के साथ बोनस

देने जैसे अनेक कदम उठाए गए। इसके कारण विगत वर्ष सर्वाधिक धान खरीदी का कीर्तिमान बना और इस साल फिर धान खरीदी जारी है। इस साल किसानों को लगभग 200 करोड़ रूपए तो सिर्फ बोनस के रूप में मिलेंगे। किसानों को विगत वर्ष लगभग 700 करोड़ रूपए के कृषि ऋण की तुलना में इस वर्ष 1300 करोड़ रूपए का ऋण मिल रहा है, वह भी देश में सबसे कम तीन प्रतिशत ब्याज दर पर। बीते 6 साल में एक लाख 60 हजार नए सिंचाई पम्प कनेक्शन दिए गए हैं। प्रति कनेक्शन खर्च की सीमा 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपए की गई। शाकम्बरी योजना, नलकूप योजना में अनुदान का लाभ हजारों किसानों को मिला है। सूक्ष्म सिंचाई योजना में किसानों को 30 प्रतिशत सबसिडी तथा उपकरण खरीदने की अन्य योजनाओं में केन्द्र सरकार से 25 प्रतिशत अतिरिक्त सबसिडी हमने दी है। कृषि उपकरणों पर वेट समाप्त किया गया है। किसान समृद्धि योजना का दायरा वृष्टि छाया क्षेत्रों से बढ़ाकर 110 विकासखण्डों तक किया गया है।

हमने अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ अब सभी वर्गों के किसानों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 'कृषक जीवन ज्योति योजना' शुरू की है। जिसमें राज्य सरकार अपनी ओर से 132 करोड़ रूपए खर्च करके, 5 हार्स पावर तक पम्पधारी किसानों को साल भर में 6 हजार रूपए की बिजली निःशुल्क देगी। इसके अलावा राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्णय से फ्लैट रेट खत्म होने और नई दरों के बीच के अंतर की राशि 15 करोड़ रूपए पटाकर हमने 35 हजार किसानों को आर्थिक संकट से उबारा है। हमने किसानों की आय बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। उन्नत प्रजाति के मंहगे बीज खरीदने में किसानों की मदद करने के लिए 'अक्ति बीज संवर्धन योजना' लागू की गई है। गन्ना किसानों को 25 रूपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया गया। गुड़ बनाने की छूट दी गई है। मछली पालकों के लिए जलाशयों की लीज अवधि दो वर्ष बढ़ाई गई है। मछली

पालन, पशु पालन तथा उद्यानिकी के लिए भी तीन प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण की सुविधा दी गई है। अपनी आजीविका के लिए वनोपज पर आश्रित लोगों की आय बढ़ाने के लिए तेन्दूपत्ता और साल बीज संग्रहण का पारिश्रमिक दोगुना तक किया गया। संग्रहकर्ताओं को पारिश्रमिक और बोनस के रूप में 250 करोड़ रूपए से अधिक राशि बीते एक साल में दी गई है। वनोपज, वनौषधि, बांस आदि के वेल्यू–एडीशन के लिए प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति अपनाई है। रोजगार गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दो जिलों को केन्द्र शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया है। इस योजना के तहत 35 लाख परिवारों को रोजगार कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। 55 लाख से अधिक श्रमिकों के खाते बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोले गए हैं। इस वर्ष मांग के आधार पर करीब 16 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। नई सुविधाओं से गांवों में रोजगार के परम्परागत अवसरों को बढ़ाया गया है। हाथकरघा, हस्तशिल्प जैसे कामों से दो लाख परिवारों को बेहतर आय का जरिया मिला है।

राज्य में औद्योगिक विकास के नए दौर का लाभ नई पीढ़ी को दिलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई जैसी संस्थाओं का जाल बिछाया जा रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की शर्त पर ही निवेशकों को रियायतों तथा सुविधाओं का लाभ देने की रणनीति अपनाई गई है। शासकीय सेवाओं में भर्ती से प्रतिबंध हटाकर हजारों लोगों को रोजगार दिया गया है। शिक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी के पदों पर भर्ती का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। खेलकूद में भी कैरियर निर्माण के अवसर बढ़ाने के लिए किए गए हमारे प्रयासों से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी अब देश की हॉकी, नेटबॉल, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल,

वेटलिफि्टिंग तथा एथलेटिक टीमों में शामिल होने लगे हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में स्थान देने का संकल्प भी हमने पूरा किया है। जिसके तहत 70 खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी गई है। नया रायपुर में छत्तीसगढ़ निर्माण एकेडमी शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से निर्माण कार्यों से जुड़े हर पहलू पर युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे राजमिस्त्री, बिजलीमिस्त्री, नलमिस्त्री, कारपेन्टर जैसे सभी कार्यों में दक्ष लोग स्थानीय स्तर पर ही मिल सकें।

हमारा मानना है कि हर व्यक्ति को रोज दो जून का भरपूर भोजन अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। भूख मुक्ति और कुपोषण मुक्ति से ही राज्य की जनता की खुशहाली का आकलन होता है। इसलिए हमने 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना' शुरू की थी और उसमें क्रमशः विस्तार करते गए। अंत्योदय परिवारों को 1 रूपए किलो में और अन्य गरीब परिवारों को 2 रूपए प्रति किलो में प्रतिमाह पैंतीस किलो चावल तथा हर गरीब परिवार को प्रति माह दो किलो आयोडाइज्ड नमक निःशुल्क देकर हमने एक और बड़ा वायदा निभाया है। गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए 'मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना' प्रारम्भ की गई है। इस काम में आंगनवाड़ी केन्द्रों को भागीदार बनाया गया है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा 13 हजार गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया है। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं से लेकर वृद्धावस्था तक के लोगों को खाद्यान्न और सुपोषण सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

हमने नई पीढ़ी को शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए बहुआयामी पहल की है। विभिन्न वर्गों की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं लागू की गई हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला है। यूपीएससी और पीएससी की परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में युवा

कैरियर निर्माण योजना के तहत तीन प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किए गए। जिसके कारण इनकी प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 100 युवा सफल हुए हैं। इन वर्गों के 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को हर साल 120 करोड़ रू. से अधिक की छात्रवृत्ति दी जा रही है। निःशुल्क नर्सिंग पाठ्यक्रम योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसका लाभ 300 बालक–बालिकाओं को मिलेगा। शिक्षित युवा बेरोजगारों के लिए वाहन चालक प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की गई है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणों के माध्यम से 362 करोड़ रूपए की लागत से 21 हजार विकास कार्यों को मंजूरी दी गई, जिससे इन अंचलों में सुविधाओं और अवसरों का विकास हुआ है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि 'पापुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया' ने छत्तीसगढ़ को शिशु मृत्यु दर में कमी तथा शिशु स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार के प्रयासों हेतु देश में अव्वल राज्य घोषित किया है। प्रदेश के 80 प्रतिशत से ज्यादा शिशु स्वास्थ्य सूचकांक अब राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गये हैं। काफी कम समय में ही प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाने में सफलता मिली है। रायगढ़ जिले में राज्य का चौथा मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 1200 से भी अधिक चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। 324 'ग्रामीण चिकित्सा सहायकों' को दूरस्थ अंचलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर नर्स तथा अन्य सहायक पदों पर भर्ती की जा रही है तथा अस्पताल भवनों का निर्माण किया जा रहा है। हमारी अभिनव योजना 'मुख्यमंत्री बाल हृदय संरक्षण योजना' के तहत 800 से अधिक बच्चों के दिल का निःशुल्क ऑपरेशन कराके उन्हें नया जीवन दिया गया है। गरीब परिवारों को स्मार्ट कार्ड के जरिए एक वर्ष में तीस हजार रूपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी। प्रथम चरण में इसका लाभ 26 हजार गरीब परिवारों को मिलेगा।

हम पर्यावरण—सम्मत विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। शहरों और गांवों का सुनियोजित विकास, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अधोसंरचना का निर्माण, सड़क, बिजली, पानी जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण में तेजी हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही हमने जलाशयों तथा हरियाली को बचाने और बढ़ाने का अभियान व्यापक जनभागीदारी से छेड़ा है। जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चिंता के मद्देनजर हम राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों में आसान पहुंच के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक इस्तेमाल एक बेहतर विकल्प है। इसलिए हमने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 'स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क' स्थापित किया है, जो गांवों और शहरों के बीच के अंतर को खत्म करने में मददगार होगा। मुझे खुशी है कि हमारी कई आईटी परियोजनाओं तथा ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को भी केन्द्र शासन ने पुरस्कारों से नवाजा है।

नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निबाहने के लिए राज्य में पुलिस बल में वृद्धि, आधुनिकीकरण और अधोसंरचना विकास के काम में तेजी लाई गई है। पुलिस बल को आतंकी और हिंसक तत्वों से निबटने के लिए यथोचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वन क्षेत्रों के विकास में नक्सलवादी तत्वों की बाधा दूर करने के बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। नक्सलवादी हिंसा में शहीद हुए अधिकारियों, पुलिस और सशस्त्र बलों के जवानों, स्थानीय निवासियों को आज फिर मैं नमन् करता हूं। मेरा अनुरोध है कि वनांचलों में रहने वाले भाई—बहनों, मासूम बच्चों का जीना दूभर कर मानव अधिकारों का हनन करने वाले नक्सली तत्वों को सबक सिखाने के लिए समाज के हर वर्ग को सहयोग करना चाहिए।

dchj rsbl ihj gSa] ts tkuSa ij ihj]
ts ij ihj u tkugha] rs dkfQj csa&ihjA

हमारी सरकार नक्सली हिंसा समाप्त करने के हर सम्भव प्रयास कर रही है लेकिन पीड़ित आबादी और सुरक्षाबलों के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपका समर्थन और सहयोग भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि आतंक और हिंसा के खिलाफ छत्तीसगढ़ की यह मुहिम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और गणतंत्र की मजबूती में अपना अहम् योगदान दर्ज करेगी।

t ; fgUn

t ; NRrhl x<